Drishti IAS

करेंट अफेयर्स उत्तर प्रदेश

जुलाई 2023

(संग्रह)

Drishti, 641, First Floor, Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009
Inquiry (English): 8010440440, Inquiry (Hindi): 8750187501
Email: help@groupdrishti.in

अनुक्रम

- पश्चिमी यूपी के नशा तस्करों पर पहली बार होगी पिट के तहत कार्रवाई 3
- बरेली की तर्ज पर देशभर में लागू होगा अन्नपूर्णा मॉडल 3
- उत्तर प्रदेश 3
- उत्तर प्रदेश के चार शहरों में बनेंगे नए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क 4
- चंबल सेंचुरी में अब जल्द ही डॉल्फिन सेंचुरी 5
- 15 जनपदों में बनेंगे आवासीय संस्कृत विद्यालय 6
- प्रधानमंत्री ने वाराणसी में 12,100 करोड़ रुपए से ज़्यादा लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया 7
- प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर रेलवे स्टेशन से दो वंदे भारत ट्रेनों को झंडी दिखाकर रवाना किया 8
- आईआईटी कानपुर ने तैयार किया आत्मघाती ड्रोन 9
- उत्तर प्रदेश कैबिनेट मीटिंग में लिये गए कई अहम फैसले 9
- काशी में होगा इंटरनेशनल टेंपल्स कन्वेंशन एंड एक्सपो 10
- वाराणसी में क्रूज, वाटर टैक्सी के बाद अब मिलेगी रोप-वे की सुविधा 12
- देशभर की खुफिया एजेंसियों से सीधे जुड़ेगा कानपुर, एक क्लिक पर मिलेगा बड़े अपराधियों का डाटा 13
- उत्तर प्रदेश आम महोत्सव-2023 14
- लखनऊ में 3,300 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश वाली दो राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शुभारंभ 16
- नीति आयोग ने जारी की रिपोर्ट : गरीबी कम करने में उत्तर प्रदेश सभी राज्यों में अव्वल 17
- अमेरिकी तकनीक से अलीगढ़ में बनेगी पिस्टल, रिवॉल्वर-कारतूस 18
- प्रदेश में खेल नीति के तहत सभी विद्यालयों में चालीस मिनट के खेल अनिवार्य 19
- अब जीवित साहित्यकारों पर भी कर सकेंगे पीएचडी, CSJMU कानपुर तैयार कर रहा लिस्ट 20
- मुख्यमंत्री ने 72 करोड़ के 42 विकास कार्यों का किया शिलान्यास 20
- जगजीवन आरपीएफ अकादमी लखनऊ में नवनिर्मित राष्ट्रीय शहीद स्मारक का अनावरण 21
- बीएचयू के डॉ. अमिय कुमार समल राष्ट्रीय युवा भूवैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित 22
- उत्तर प्रदेश में स्थापित होगा आपदा राहत प्रशिक्षण केंद्र 23
- उत्तर प्रदेश के 74 ज़िलों में खुलेंगे क्रिटिकल केयर यूनिट 24

नोट :

उत्तर प्रदेश

पश्चिमी यूपी के नशा तस्करों पर पहली बार होगी पिट के तहत कार्रवाई

चर्चा में क्यों ?

29 जून, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार पश्चिमी यूपी में पहली बार नशा तस्करों पर पिट (द प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिक इन नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक एंड सबस्टांसेंस एक्ट-1988) के तहत कार्रवाई होने जा रही है।

प्रमुख बिंदु

- जानकारी के अनुसार सहारनपुर से लेकर शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, बिजनौर, मेरठ, हापुड़ और बुलंदशहर की जेलों में बंद उन तस्करों की फाइल तैयार की जा रही है, जो नशा तस्करी के आदतन अपराधी हो चुके हैं और जेल से बाहर निकलने के बाद वह फिर इसी धंधे में शामिल हो सकते हैं।
- पिट की कार्रवाई के लिये करीब 20 तस्करों की फाइल तैयार की जा रही है। यह कार्रवाई एएनटीएफ (एंटी नारकोटिक्स टॉस्क फोर्स) की ओर से कराई जाती है।
- एएनटीएफ ने जिन तस्करों की फाइल पिट के लिये तैयार की है, उसे डीएम से कमिश्नर और मुख्यालय भेजा जाएगा। शासन स्तर पर जाँच होगी कि जिस व्यक्ति के खिलाफ पिट की कार्रवाई की फाइल आई है वह कितनी जायज है। शासन की अनुमति के बाद कार्रवाई की जाएगी।
- पुलिस उपाधीक्षक एनएनटीएफ मेरठ-सहारनपुर राजेश कुमार के मुताबिक पश्चिमी यूपी में अभी तक ऐसी कार्रवाई नहीं हुई थी। इस कार्रवाई के बाद नशा तस्कर कम से कम एक साल जेल के अंदर रहेगा और जमानत से लेकर अन्य किसी तरह की याचिका पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।
- इसके अलावा नशे के धंधे से उसने जो संपत्ति जुटाई थी, उसे भी सर्वे कर जब्त किया जाएगा। यह कार्रवाई उन अपराधियों के खिलाफ कराई जाती है, जिनका जेल में बंद रहना जरूरी हो जाता है।
- उल्लेखनीय है कि पिट की कार्रवाई एनएसए (राष्ट्रीय सुरक्षा कानून) से मिलती-जुलती है। एनएसए के तहत किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को तीन महीने बिना जमानत के हिरासत में रखा जा सकता है। ज़रूरत पड़ने पर तीन-तीन माह की अवधि बढ़ाई जा सकती है, जो अधिकतम एक साल हो सकती है।
- हिरासत में रखने के लिये संदिग्ध पर आरोप तय करने की ज़रूरत नहीं होती। हालाँकि प्रदेश सरकार को यह बताना पड़ता है कि इस व्यक्ति को जेल में किस आधार पर रखा गया। यह कार्रवाई शासन के आदेश पर सिविल पुलिस कर सकती है, जबकि पिट की कार्रवाई सिर्फ एएनटीएफ कर सकती है।

बरेली की तर्ज पर देशभर में लागू होगा अन्नपूर्णा मॉडल

चर्चा में क्यों ?

29 जून, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार ने बरेली के अन्नपूर्णा मॉडल को पूरे देश में लागू करने के निर्देश दिये हैं। इसके तहत राशन की उचित दर की दुकानों को अन्नपूर्णा स्टोर में शिफ्ट किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- विदित है कि बरेली मंडल की कमिश्नर सौम्या अग्रवाल और बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) के उपाध्यक्ष जोगिंदर सिंह ने 17 मई को मंडल में बनाए जा रहे 52 अन्नपूर्णा स्टोर्स का मॉडल मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया था। अन्नपूर्णा मॉडल के तहत उचित दर की दुकान एवं जन सुविधा केंद्र होगा, जिसे 'अन्नपूर्णा स्टोर' का नाम दिया गया है।

नोट :

- कमिश्नर सौम्या अग्रवाल ने बताया कि डोर स्टेप डिलीवरी की सिंगल स्टेज व्यवस्था के तहत खाद्यान्न के वाहनों का उचित दर की दुकान तक आसानी से पहुँचना ज़रूरी है। इसलिये ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सभाएँ व शहरी क्षेत्रों में नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर निगम अपने आर्थिक स्रोतों, मनरेगा आदि योजनाओं से राशन की दुकानों का निर्माण कराएंगे।
- उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने इन दुकानों को ऐसी जगह बनाने का आदेश दिया है, जहाँ आम लोगों की पहुँच आसान हो। यानी दुकानें गली-कूचों में न होकर खुले या सहज पहुँच वाले स्थानों पर हों।
- दुकानों का निर्माण ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत भवन व शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक भवनों के नज़दीक किये जाएंगे। इस मॉडल पर बरेली में कई दुकानें अभी निर्माणाधीन हैं। ज़िले के सभी ब्लॉकों में इन दुकानों का निर्माण कराया जाएगा। केंद्र सरकार ने इसी मॉडल को पूरे देश में लागू करने के निर्देश दिये हैं।
- अन्नपूर्णा स्टोर के जनसुविधा केंद्र से आय, जाति, जन्म, निवास प्रमाण-पत्र, आधार, पेंशन व अन्य सेवाएँ मिलेंगी। विभिन्न प्रकार के बिल जमा किये जा सकेंगे। अन्नपूर्णा स्टोर में पाँच किलोग्राम वाले एलपीजी सिलिंडर, ई-स्टांप, अग्निशमन यंत्र मिलेंगे। माइक्रो एटीएम, बीसी सखी आदि की सेवाएँ भी मिलेंगी।

उत्तर प्रदेश के चार शहरों में बनेंगे नए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क

चर्चा में क्यों ?

3 जुलाई, 2023 को सॉफ्टवेयर टेक्नोलाजी पार्क्स आफ इंडिया के अपर निदेशक डॉ. प्रवीण कुमार द्विवेदी ने बताया कि उत्तर प्रदेश के चार शहरों आगरा, बरेली, गोरखपुर और वाराणसी में नए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के निर्माण पर काम शुरू हो गया है। आगरा सॉफ्टवेयर पार्क अगस्त में शुरू हो जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- डॉ. प्रवीण कुमार द्विवेदी ने बताया कि सॉफ्टवेयर सेक्टर में उत्तर प्रदेश का रुतबा और मजबूत होगा। इसके लिये केंद्र के सहयोग से प्रदेश सरकार द्वारा चार और शहरों में सॉफ्टवेयर टेक्नोलाजी पार्क की स्थापना मूर्त रूप लेने लगी है।
- छोटे शहरों में सॉफ्टवेयर पार्क खोलने का मकसद एक तरफ अपने ही शहर में हाईटेक युवाओं को रोज़गार मुहैया कराना है तो दूसरी तरफ सॉफ्टवेयर निर्यात में तेजी लाना भी है।
- वर्तमान में कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, नोएडा और मेरठ में सॉफ्टवेयर टेक्नोलाजी पार्क हैं। केंद्र और राज्य की संयुक्त पहल के तहत आगरा, बरेली, गोरखपुर और वाराणसी में भी नए साफ्टवेयर पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी गई थी। फिजिबिलिटी रिपोर्ट में ये सभी शहर पास हो गए।
- वर्तमान में चल रहे सॉफ्टवेयर पार्कों में 400 इकाइयाँ कार्यरत हैं। नए सॉफ्टवेयर पार्कों में करीब 200 इकाइयाँ आने का अनुमान है। प्रत्येक पार्क में न्यूनतम 1200 से 1300 सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स को रोज़गार मिलेगा।
- चुने गए शहरों में पहले चरण में 20-20 हज़ार वर्गफुट की इमारतों का निर्माण कराया जाएगा। आगरा में पार्क लगभग तैयार है। वाराणसी को छोड़कर बरेली और गोरखपुर में तेजी से काम हो रहा है। फिर मांग के अनुसार उसमें वृद्धि की जाएगी। फिलहाल चारों पार्कों में करीब 80 करोड़ रुपए का बजट निर्माण के लिये रखा गया है।
- छोटे शहरों के सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स के पास सीमित अवसर हैं इसीलिये अपना घर छोड़कर दूसरी जगह नौकरी करना उनकी मज़बूरी है। छोटे शहरों में सॉफ्टवेयर पार्कों की स्थापना का एक मकसद ये भी है कि हर ज़िले में कंप्यूटर दक्ष युवाओं के लिये रोज़गार के अवसर खोले जा सकें। वृद्धावस्था में एकाकी जीवन जी रहे बुजुर्ग माँ-बाप अपने बच्चों के साथ रहें।
- दूसरी तरफ सॉफ्टवेयर के निर्यात में उत्तर प्रदेश में सालाना 12 फीसदी से ज्यादा की ग्रोथ है जो बढ़कर 20 फीसदी हो सकता है। दो साल में उत्तर प्रदेश से सॉफ्टवेयर निर्यात 28 से बढ़कर 34 हज़ार करोड़ रुपए हो गया है। 2020-21 में 28 हज़ार करोड़ रुपए, 2021-22 में 31 हज़ार करोड़ रुपए और 2022-23 में 34 हज़ार करोड़ रुपए के सॉफ्टवेयर का निर्यात हुआ।

चंबल सेंचुरी में अब जल्द ही डॉल्फिन सेंचुरी

चर्चा में क्यों?

5 जुलाई, 2023 को राष्ट्रीय चंबल सेंचुरी प्रोजेक्ट की उप वन संरक्षक (वन्यजीव) आरुषि मिश्रा ने बताया कि चंबल सेंचुरी में अब जल्द ही डॉल्फिन सेंचुरी क्षेत्र भी घोषित होगा। राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन के संरक्षण के लिये डॉल्फिन सेंचुरी का एक प्रस्ताव शासन को भेजा गया है।

प्रमुख बिंदु

- आरुषि मिश्रा ने बताया कि घड़ियाल, मगरमच्छ, कछुए, पक्षियों और प्राकृतिक सुंदरता से गुलजार चंबल सेंचुरी में अब जल्द ही डॉल्फिन सेंचुरी क्षेत्र भी घोषित होगा। डॉल्फिन सेंचुरी के लिये इटावा स्थित राष्ट्रीय चंबल सेंचुरी के सहसों क्षेत्र का चयन किया गया है, जहाँ बड़ी संख्या में डॉल्फिन पाई जाती हैं।
- इटावा स्थित चंबल सेंचुरी के सहसों के 20 किमी. क्षेत्र में बड़ी संख्या में डॉल्फिन पाई जाती है। यहाँ पर डॉल्फिन की संख्या में लगातार इज़ाफा देखा जा रहा है। इस स्थान पर 50 से 80 के करीब डॉल्फिन पाई जाती हैं।
- विदित है कि 2012 में उत्तर प्रदेश की नदियों में डॉल्फिन की हुई गणना में डॉल्फिन की संख्या 671 थीं, जिसमें से 78 चंबल में थीं। इस समय राष्ट्रीय चंबल सेंचुरी क्षेत्र के बाह रेंज में 24 और इटावा रेंज में 147 डॉल्फिन हैं।
- उप वन संरक्षक (वन्यजीव) आरुषि मिश्रा ने बताया कि साल 1979 में घोषित हुए राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य 635 वर्ग किमी. क्षेत्रफल में फैला है। यह मध्य प्रदेश, राजस्थान व उत्तर प्रदेश तीन राज्यों को जोड़ता है।
- इसमें साल 2008 से घड़ियालों की प्राकृतिक हैचिंग हो रही है। परिणामस्वरूप घड़ियालों की संख्या 2,176 पहुँच गई है। 878 मगरमच्छ के साथ उत्तर प्रदेश के इटावा तक करीब छह हज़ार दुर्लभ प्रजाति के कछुए पाए जाते हैं। वहीं, चंबल सेंचुरी में संरक्षित राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन का कुनबा भी बढ़ा है।
- आरुषि मिश्रा ने बताया कि डॉल्फिन सफारी के लिये भारत सरकार ने दो स्थानों को प्रमुखता दी है। बीते दिनों वाराणसी और चंबल का प्रेजेंटेशन भारत सरकार के सामने हो चुका है। यह इको टूरिज्म और डॉल्फिन कंजर्वेशन की दिशा में भी सरकार का बड़ा कदम है।
- गौरतलब है कि गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है। गंगा डॉल्फिन को वर्ष 2009 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय जलीय जीव (National Aquatic Animal) के रूप में मान्यता दी थी।
- **संरक्षण स्थिति:**
  - भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-I के तहत गंगा डॉल्फिन का शिकार करना प्रतिबंधित है।
  - गंगा डॉल्फिन को IUCN की रेड लिस्ट में संकटग्रस्त (Endangered) की श्रेणी में रखा गया है।
  - गंगा डॉल्फिन को 'वन्यजीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन'(The Convention of International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora& CITES) के परिशिष्ट-I में शामिल किया गया है।
  - वन्यजीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर अभिसमय (CMS)% परिशिष्ट II (प्रवासी प्रजातियाँ जिन्हें संरक्षण और प्रबंधन की आवश्यकता है या जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से काफी लाभ होगा)।
- **संरक्षण के लिये उठाए गए कदम:**
  - प्रोजेक्ट डॉल्फिन: भारत के प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस-2020 पर दिये गए अपने भाषण में प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लॉन्च करने की घोषणा की। यह प्रोजेक्ट टाइगर की तर्ज पर होगा, जिसने बाघों की आबादी बढ़ाने में मदद की।
  - डॉल्फिन अभयारण्य: बिहार के भागलपुर ज़िले में विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य की स्थापना की गई है।
  - संरक्षण योजना: 'गंगा डॉल्फिन संरक्षण कार्य योजना 2010-2020' गंगा डॉल्फिन के संरक्षण के प्रयासों में से एक है, इसके तहत गंगा डॉल्फिन और उनकी आबादी के लिये प्रमुख खतरों के रूप में नदी में यातायात, सिंचाई नहरों और शिकार की कमी आदि की पहचान की गई है।
  - राष्ट्रीय गंगा डॉल्फिन दिवस: राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा प्रतिवर्ष 5 अक्तूबर को गंगा डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता है।

नोट :

15 जनपदों में बनेंगे आवासीय संस्कृत विद्यालय

चर्चा में क्यों ?

6 जुलाई, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश में धार्मिक स्थलों के रूप में विकसित किये जा रहे जनपदों में राज्य सरकार द्वारा संस्कृत भाषा के उन्नयन पर जोर देने के लिये ब्रज के मथुरा और एटा समेत प्रदेश के और कई जनपदों में नवीन उत्तर मध्यमा (मध्यवर्ती स्तर के) आवासीय संस्कृत विद्यालयों की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है।

प्रमुख बिंदु

- मथुरा, एटा के अलावा वाराणसी, रायबरेली, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, जालौन, अमेठी, मुरादाबाद, हरदोई, गोरखपुर, अयोध्या, प्रयागराज, चित्रकूट सहित कुल 15 जनपदों में नवीन आवासीय राजकीय संस्कृत माध्यमिक विद्यालय खोलने की तैयारी शुरू कर दी गई है।
- इन विद्यालयों में छात्रों को पौरोहित्य (कर्मकांड), व्यवहारिक वास्तुशास्त्र, व्यवहारिक ज्योतिष तथा योग विज्ञानम् में एक वर्षीय डिप्लोमा मिलेगा। डिप्लोमा पाठ्यक्रम मान्यता प्राप्त विद्यालयों में स्ववित्तपोषित आधार पर संचालित होंगे।
- पाठ्यक्रम एक वर्षीय तथा दो सेमेस्टर में विभाजित होगा। इंटर्नशिप के माध्यम से व्यवहारिक ज्ञान पर अधिक बल दिया जाएगा। इन पाठ्यक्रमों में उत्तर मध्यमा (कक्षा 12वीं) या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी प्रवेश के लिये पात्र होंगे। इसमें उच्च परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी प्रवेश ले सकते हैं। प्रवेश के लिये कोई आयु सीमा नहीं होगी।
- परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार करते हुए राज्य सरकार ने ऑनलाइन परीक्षा आवेदन, अग्रिम पंजीकरण और परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी की निगरानी में संस्कृत विद्यालयों में परीक्षा की व्यवस्था प्रारंभ करने का भी निर्णय लिया है।
- संस्कृत विद्यालयों में डिप्लोमा पाठ्यक्रम चलाने के लिये अध्यापकों की व्यवस्था प्रबंध समिति द्वारा अपने निजी स्त्रोतों के माध्यम से की जाएगी। इन विद्यालयों को साज-सज्जा और फर्नीचर इत्यादि के लिये धनराशि भी प्रथम बार दी जाएगी। सहायता प्राप्त संस्कृत विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिये प्रथम बार पारदर्शी चयन प्रक्रिया होगी।
- प्रदेश सरकार ने नवीन संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों की मान्यता देना भी प्रारंभ किया है। ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से प्रदेश में 48 संस्थाओं को नवीन मान्यता प्रदान की गई है।

नोट :

- राजकीय और सहायता प्राप्त संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिये निशुल्क पाठ्यपुस्तकों और मध्याह्न भोजन की व्यवस्था कराई गई है।
- पारंपरिक विषयों के साथ आधुनिक विषयों एवं एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम का समावेश करते हुए संस्कृत शिक्षा के आधुनिकीकरण व प्रसार के लिये संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रम लागू किया गया है।
- वर्तमान में पूरे राज्य में केवल एक राजकीय संस्कृत माध्यमिक और एक राजकीय संस्कृत डिग्री कॉलेज संचालित है। इसके अलावा संस्कृत की पढ़ाई करवाने वाले अन्य सभी संस्थान निजी तौर पर चलाए जा रहे हैं।
- उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में संस्कृत स्कूलों को खोलने की घोषणा 2023-24 के बजट में की गई थी। इसके लिये बजट में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था।

प्रधानमंत्री ने वाराणसी में 12,100 करोड़ रुपए से ज़्यादा लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया

चर्चा में क्यों ?

7 जुलाई, 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 12,100 करोड़ रुपए से ज़्यादा की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया।

प्रमुख बिंदु

- प्रधानमंत्री ने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन-सोन नगर रेलवे लाइन को समर्पित किया। 6760 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाई गई नई लाइन माल की तेज और अधिक कुशल आवाजाही की सुविधा प्रदान करेगी।
- उन्होंने राष्ट्र को तीन रेलवे लाइनें भी समर्पित कीं, जिनका 990 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से विद्युतीकरण या दोहरीकरण किया गया है। इनमें गाजीपुर शहर-औंरिहार रेल लाइन, औंरिहार-जौनपुर रेल लाइन और भटनी-औंरिहार रेल लाइन शामिल हैं। इन परियोजनाओं से उत्तर प्रदेश में रेलवे लाइनों के 100 प्रतिशत विद्युतीकरण को हासिल करने में मदद मिली है।
- प्रधानमंत्री ने एनएच-56 के वाराणसी-जौनपुर खंड के चार लेन चौड़ीकरण को राष्ट्र को समर्पित किया, जिसे 2,750 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया गया है और इससे वाराणसी से लखनऊ के लिये सफर आसान और तेज हो गया है।
- प्रधानमंत्री ने जिन परियोजनाओं का शिलान्यास किया, उनमें चौखंडी, कादीपुर और हरदत्तपुर रेलवे स्टेशनों के पास दो लेन वाले तीन रेल ओवर ब्रिज (आरओबी); व्यासनगर- पं. दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रेल फ्लाईओवर का निर्माण; और पीडब्ल्यूडी की 15 सड़कों का निर्माण एवं नवीकरण शामिल है। इन परियोजनाओं को लगभग 780 करोड़ रुपए की कुल लागत से विकसित किया जाएगा।
- प्रधानमंत्री ने जल जीवन मिशन के तहत 550 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनने वाली 192 ग्रामीण पेयजल योजनाओं की आधारशिला भी रखी। इससे 192 गाँवों के 7 लाख लोगों को शुद्ध पेयजल मिलेगा।
- प्रधानमंत्री ने मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाटों के पुन: डिजाइन और पुनर्विकास की आधारशिला भी रखी। पुनर्विकसित किये गए घाटों में सार्वजनिक सुविधाएँ, प्रतीक्षा क्षेत्रों, लकड़ी भंडारण, अपशिष्ट निपटान और पर्यावरण-अनुकूल दाह संस्कार के प्रावधान होंगे।
- जिन अन्य परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई उनमें दशाश्वमेध घाट के फ्लोटिंग चेंजिंग रूम जेटी की तर्ज पर वाराणसी में गंगा नदी पर छह धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण स्नान घाटों पर फ्लोटिंग चेंजिंग रूम जेटी और सीआईपीईटी परिसर करसरा में छात्रों के छात्रावास का निर्माण शामिल है।
- कार्यक्रम के दौरान, प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में लाभार्थियों को पीएम स्वनिधि के ऋण, पीएमएवाई ग्रामीण घरों की चाबियां और आयुष्मान भारत कार्ड भी वितरित किये। इससे 5 लाख पीएमएवाई लाभार्थियों का गृह प्रवेश, पात्र लाभार्थियों को 1.25 लाख पीएम स्वनिधि ऋण का वितरण और 2.88 करोड़ आयुष्मान कार्ड का वितरण शुरू हो जाएगा।

नोट :

प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर रेलवे स्टेशन से दो वंदे भारत ट्रेनों को झंडी दिखाकर रवाना किया

चर्चा में क्यों ?

7 जुलाई, 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर रेलवे स्टेशन से दो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों- गोरखपुर-लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस और जोधपुर-अहमदाबाद (साबरमती) वंदे भारत एक्सप्रेस को झंडी दिखाकर रवाना किया।

प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर प्रधानमंत्री के साथ उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गोरखपुर से सांसद रवि किशन भी मौजूद थे।
- गोरखपुर-लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस अयोध्या से होकर गुजरेगी और पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ राज्य के महत्त्वपूर्ण शहरों के रेल-परिवहन संपर्क में सुधार करेगी।
- जोधपुर-साबरमती वंदे भारत एक्सप्रेस, क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हुए जोधपुर, आबू रोड और अहमदाबाद जैसे प्रसिद्ध स्थानों के लिये रेल-परिवहन संपर्क का विस्तार करेगी।
- लगभग 498 करोड़ रुपए की लागत से गोरखपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास का शिलान्यास भी किया गया है। पुनर्विकसित होने के बाद, गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को विश्वस्तरीय सुविधाएँ प्राप्त होंगी।

आईआईटी कानपुर ने तैयार किया आत्मघाती ड्रोन

चर्चा में क्यों ?

10 जुलाई, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार दुश्मनों की खोजखबर की जानकारी देने वाले ड्रोन के सफल संचालन के बाद अब आईआईटी कानपुर ने आत्मघाती ड्रोन तैयार किया है। यह ड्रोन दुश्मन के ठिकाने पर जाकर खुद ही फट जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- जानकारी के अनुसार आईआईटी के एयरोस्पेस इंजीनियरिंग विभाग के वैज्ञानिक डॉ. सुब्रमण्यम सडरेला और उनकी टीम ने इसे विकसित किया है।
- यह आत्मघाती ड्रोन भारतीय सीमा से 100 किमी. की दूरी तय कर वार करेगा। 100 किमी. पहुँचने में इसे 40 मिनट का समय लगेगा।
- आईआईटी के एयरोस्पेस इंजीनियरिंग विभाग के वैज्ञानिक डॉ. सुब्रमण्यम सडरेला ने बताया कि दुश्मनों की रडार में न आने के लिये इसमें स्टेल्ड तकनीक का इस्तेमाल किया गया है।
- यह ड्रोन अल्गोरिदम के हिसाब से चलता है। मतलब, यह खुद भी फैसला ले सकेगा और इसे बेस स्टेशन से रिमोट से भी नियंत्रित किया जा सकता है। ड्रोन निर्धारित टारगेट से सिर्फ दो मीटर ही भटक सकता है। यह दिन के अलावा रात में भी उड़ान भरने में सक्षम है।
- प्रो. सडरेला ने बताया कि डीआरडीओ के डीवाईएसएल प्रोजेक्ट के तहत एक साल से इस ड्रोन पर रिसर्च काम चल रहा है। यह दो मीटर लंबा फोल्डेबल फिक्स्ड विंग वाला ड्रोन है। यह 100 मीटर से साढ़े चार किमी. की ऊँचाई तक उड़ने में सक्षम है।
- प्रो. सडरेला ने बताया कि यह ड्रोन स्वदेशी तकनीक से विकसित किया गया है। यह आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (एआई) तकनीक पर काम करेगा। इस ड्रोन में सेना की जरूरतों के मुताबिक बदलाव भी संभव होगा।
- ड्रोन की विंग में कैमरे और इंफ्रारेड सेंसर लगे हैं। इसे कैटपल्ट या कैनिस्टर लांचर से लांच किया जा सकता है। एआई तकनीक की मदद से यह ड्रोन जीपीएस ब्लॉक होने के बाद भी टॉरगेट को तबाह कर देगा।
- ड्रोन पर आईआईटी के वैज्ञानिक लगातार रिसर्च कर रहे हैं। आपदा और सेना की ज़रूरतों के मुताबिक रिसर्च कर ड्रोन विकसित किया जा रहा है। ड्रोन छह महीने के ट्रायल के बाद पूरी तरह से तैयार हो जाएगा।

उत्तर प्रदेश कैबिनेट मीटिंग में लिये गए कई अहम फैसले

चर्चा में क्यों ?

11 जुलाई, 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी।

प्रमुख बिंदु

- प्रमुख महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव जिन पर मुहर लगी हैं, वे हैं-:
    - एनटीपीसी के सहयोग से ओबरा सोनभद्र में 800 मेगावाट के 2 प्लांट लगेंगे। यह राज्य का पहला अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्लांट है। इसकी कुल लागत 1800 करोड़ रुपए आएगी। इस प्लांट के नज़दीक ही कोयले की खदान है, जिसके बनने से उपभोक्ताओं को बिजली एक रुपया सस्ती मिलेगी।
    - रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व होगा।
    - मत्रिमंडल की मीटिंग में 35 करोड़ पौध रोपण कराने के लिये व्यापक कार्ययोजना बनाई गई।
    - स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा संचालित सभी प्रकार के गृहों में रहने वाले बच्चों को प्रतिमाह अब 4000 रुपए दिया जाएगा।
    - जल निगम नगरीय के नियमित 267 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को नगर निकायों में खाली पड़े पदों पर समायोजित किया जाएगा।

काशी में होगा इंटरनेशनल टेंपल्स कन्वेंशन एंड एक्सपो

चर्चा में क्यों ?

12 जुलाई, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार टेंपल कनेक्ट की तरफ से पहली बार वाराणसी में 22 से 24 जुलाई तक दुनिया के बड़े मंदिरों का सम्मेलन इंटरनेशनल टेंपल्स कन्वेंशन एंड एक्सपो (आईटीसीएक्स) का आयोजन किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- सम्मेलन का उद्घाटन राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) सरसंघचालक मोहन भागवत 22 जुलाई को करेंगे। इसमें मंदिरों के न्यासी, त्रावणकोर के राजकुमार (पद्मनाभस्वामी मंदिर), गोवा के पर्यटन मंत्री रोहण ए. खुंते, तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के कार्यकारी अधिकारी धर्म रेड्डी भी शामिल रहेंगे।
- सम्मेलन में 25 देशों के 450 से ज्यादा मंदिरों के पदाधिकारी हिस्सा लेंगे। हिन्दू के साथ ही सिख, बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित मठ, मंदिर व गुरुद्वारों के पदाधिकारी भी आएंगे।
- पूरा कार्यक्रम रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में होगा। टेंपल कनेक्ट की तरफ से पहली बार इंटरनेशनल टेंपल्स कन्वेंशन एंड एक्सपो (आईटीसीएक्स) का आयोजन किया जा रहा है। इसमें मंदिर प्रबंधन, संचालन व प्रशासन के विकास, सशक्तीकरण पर चर्चा की जाएगी।

नोट :

- टेंपल कनेक्ट के संस्थापक गिरेश कुलकर्णी, आईटीसीएक्स के चेयरमैन प्रसाद लाड और को-क्यूरेटर मेघा घोष ने बताया कि पूरे विश्व में पूजा स्थल प्रधान की टीमों के लिये सर्वश्रेष्ठ कार्यपद्धति विकसित की जाएगी। स्थापना के साथ ही विकास व सक्षम बनाने की मुहिम आगे बढ़ाई जाएगी।
- तीन दिवसीय कार्यक्रम अतुल्य भारत अभियान का हिस्सा है। इसमें पर्यटन मंत्रालय भी सहयोग कर रहा है। सम्मलेन के दौरान मंदिर, मठ और गुरुद्वारों में आने वाले तीर्थयात्रियों के अनुभव, भीड़ प्रबंधन, ठोस कचरा प्रबंधन और बुनियादी सुविधाओं में सुधार जैसे विषयों पर चर्चा भी की जाएगी।
- सम्मलेन में जैन धर्मशालाओं, प्रमुख भक्ति धर्मार्थ संगठन, यूनाइटेड किंगडम के हिन्दू मंदिरों के संघ, इस्कॉन मंदिर, अन्न क्षेत्र प्रबंधन, विभिन्न तीर्थ स्थलों के पुरोहित महासंघ और विभिन्न तीर्थयात्रा संवर्धन परिषद के प्रतिनिधि भाग लेंगे।
- यह सम्मेलन एक प्लेटफॉर्म का काम करेगा, जहाँ पूरे विश्व के धर्मस्थलों की विविध संस्कृतियों, परंपराओं, कला और शिल्प के बारे में सीखने के साथ-साथ भारत की समृद्ध पूजा स्थल धरोहर से दुनिया भी रूबरू होगी।
- सम्मेलन में हरित ऊर्जा, पुरातात्त्विक वास्तुशिल्प, लंगर प्रबंधन, प्रकाश व्यवस्था पर चर्चा होगी। तिरुपति बालाजी पूजास्थल के विशेषज्ञ पंक्ति प्रबंधन प्रणाली और वाराणसी के घाटों की सफाई व रखरखाव करने वाले सामाजिक संगठन के लोग भी शामिल होंगे।
- सत्रों को काशी विश्वनाथ मंदिर, महाकाल ज्योतिर्लिंग, अयोध्या राम मंदिर, पटना साहेब गुरुद्वारा, चिदंबरम मंदिर और विरूपक्ष मंदिर हंपी के प्रतिनिधि संचालित करेंगे।
- अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन-2023: टेंपल कनेक्ट द्वारा संचालित अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन और एक्सपो, (आईटीसीएक्स), मंदिर प्रबंधन पर अपनी सर्वोत्तम प्रथाओं, सीख और अमूल्य अंतर्दृष्टि को साझा करने के लिये दुनिया भर के मंदिरों का एक समूह है। यह संपूर्ण मंदिर पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत और सशक्त बनाने की दिशा में एक गहरा प्रयास है।
- इसके अतिरिक्त, यह सम्मेलन दुनिया भर के मंदिरों की विविध संस्कृतियों, परंपराओं और कला और शिल्प के बारे में जानने का एक अद्भुत स्थान है।
- उल्लेखनीय है कि टेंपल कनेक्ट एक अग्रणी मंच और वैश्विक हिन्दू मंदिर को जोड़ने और भक्तों के लाभ के लिये सभी को जानकारी का डिजिटल प्रारूप प्रदान करने की एक पहल है। इसकी स्थापना गिरेश कुलकर्णी ने वर्ष 2016 में की थी।

वाराणसी में क्रूज, वाटर टैक्सी के बाद अब मिलेगी रोप-वे की सुविधा

चर्चा में क्यों ?

12 जुलाई, 2023 को उत्तर प्रदेश की धार्मिक नगरी वाराणसी के मंडलायुक्त कौशलराज शर्मा ने बताया कि वाराणसी में जाम से निजात दिलाने के क्रम में गंगा में जलपरिवहन को बढ़ावा देने के लिये पहले क्रूज और वाटर टैक्सी के संचालन के बाद अब देश में पहली बार ट्रांसपोर्टेशन के लिये रोप-वे संचालन शुरू होने जा रहा है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- पहले चरण में रोप-वे कैंट स्टेशन से करीब चार किमी. की यात्रा कराएगा। दूसरे चरण में बीएचयू और सारनाथ की भी सैर का मौका मिलेगा।
- पहले चरण में कैंट से गोदौलिया तक रोप-वे पर काम शुरू हो गया है, जिसे दिसंबर 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। गोदौलिया तक रोप-वे का संचालन शुरू होने के बाद दूसरे चरण में चौक, मैदागिन, गोलगड्डा से नमोघाट के आसपास तक एक लाइन दौड़ाई जाएगी।
- दूसरी लाइन नमोघाट से सारनाथ के बीच में होगी, जो आशापुर होती हुई जाएगी। वहीं, गोदौलिया से तीसरी लाइन मदनपुरा, सोनारपुरा, ब्रॉडवे होटल, रवींद्रपुरी तथा रविदास गेट होते हुए बीएचयू परिसर तक होगी।
- इनके अलावा, एक अन्य लाइन को घाटों से जोड़ने के लिये रविदास घाट तक ले जाने की भी योजना है।
- वर्तमान में चल रहे प्रोजेक्ट के अंतर्गत कैंट से गोदौलिया तक चार किमी. लंबे रूट पर पाँच स्टेशन होंगे। कैंट स्टेशन के पास एक मिनी होटल और लाकर रूम भी होगा। विश्वनाथ मंदिर दर्शन के लिये आने वाले पर्यटक सबसे ज्यादा इसी रूट से गोदौलिया चौराहे तक जाते हैं। निर्माण की जिम्मेदारी विश्व समुद्रा को दी गई है।
- 18 माह में पूरा होने वाला रोप-वे प्रोजेक्ट देश का पहला प्रोजेक्ट है, जो शहरी परिवहन का हिस्सा होगा।
- प्रति घंटे तीन हज़ार यात्रियों को रोप-वे की केबल कार में सफर कराया जाएगा। रोप-वे में 228 केबिन होंगे। एक केबिन में 10 लोग सवार हो सकेंगे तथा 6.5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से 17 मिनट में दूरी तय कर ली जाएगी।

देशभर की खुफिया एजेंसियों से सीधे जुड़ेगा कानपुर, एक क्लिक पर मिलेगा बड़े अपराधियों का डाटा

चर्चा में क्यों?

13 जुलाई, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार अपराधियों पर लगाम और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिये उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर को जल्द मैक (मल्टी एजेंसी सेंटर) से जोड़ दिया जाएगा, जिससे देश के किसी भी अपराधी की तस्वीर व उसकी पूरी जानकारी एक क्लिक पर हासिल हो जाएगी।

प्रमुख बिंदु

- कानपुर शहर को मैक (मल्टी एजेंसी सेंटर) से जोड़ने से आईबी, एनआईए, रॉ, एटीएस जैसी तमाम इंटेलीजेंस एजेंसियाँ सीधे इस शहर से इनपुट साझा कर सकेंगी।

नोट :

- विदित है कि पहले यह सिस्टम सिर्फ राज्य मुख्यालयों तक ही सीमित था, अब शहरों में भी इन्हें स्थापित किया जाएगा इसलिये इसे एसमैक (सब्सिडेरी मल्टी एजेंसी सेंटर) कहा जाएगा। कानपुर के अलावा प्रदेश के 78 शहरों को इसमें शामिल किया गया है।
- मैक को क्राइम ब्रांच में इंस्टाल किया जाएगा। जो सिस्टम क्राइम ब्रांच में लगेगा, उसमें एक इंट्रानेट लाइन होगी, जो कि एक प्राइवेट नेटवर्क होता है। इसे संबंधित व्यक्ति ही अपनी लॉगइन आईडी के साथ इस्तेमाल कर सकता है। इसे इंटरनेट की तरह हर कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता।
- इससे एक हाई सिक्योर्ड टेलीफोन लाइन जुड़ी होगी जिसे हॉट लाइन भी कहते हैं। हर खुफिया एजेंसी से एक अफसर (वन प्वाइंट कॉनटेक्ट) इस सिस्टम को हैंडल करेगा।
- इससे आतंकी गतिविधियाँ, बड़े पैमाने पर मादक पदार्थ, सोना और नकली नोटों की तस्करी जैसे बड़े अपराधों की सूचना पुलिस को एक कॉल पर उनके सिस्टम पर उपलब्ध होगी। कानपुर में बैठे पुलिस अफसर पता लगा सकेंगे कि यहां का रहने वाला अपराधी देश के किन-किन शहरों में क्या-क्या अपराध कर चुका है। इसी तरह दूसरे शहर से आए अपराधियों की भी जानकारी आसानी से हो जाएगी। यह इनपुट यहाँ की पुलिस चंद सेकेंड में पूरे देश को दे सकेगी।
- गौरतलब है कि 3 मई, 1999 से 26 जुलाई, 1999 के बीच कारगिल युद्ध के बाद मैक की स्थापना हुई। इसकी नोडल एजेंसी आईबी को बनाया गया था।
- ज्ञातव्य है कि अब तक मैक सिर्फ राज्यों को दिया गया था। इसमें उत्तर प्रदेश में इसका सिस्टम एसटीएफ के पास था। हालाँकि बाद में एक सिस्टम एटीएस में भी इंस्टाल किया गया था।
- इस सिस्टम को लगाने का मुख्य उद्देश्य साइबर स्पेस के अवैध इस्तेमाल, क्राइम टेरर नेक्सस, नार्को-टेररिज्म, टेरर फाइनेंसिंग, ग्लोबल टेरर ग्रुप्स, विदेशी आतंकवादियों की आवाजाही की जानकारियाँ हासिल कर एजेंसियों से साझा करना है। इसे यूएन (यूनाइटेड नेशन) की सीआईसी (सेंट्रल इंटेलीजेंस एजेंसी) के आधार पर बनाया गया है।

उत्तर प्रदेश आम महोत्सव-2023

चर्चा में क्यों?

14 से 16 जुलाई, 2023 तक उत्तर प्रदेश के उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा लखनऊ के अवध शिल्पग्राम में उत्तर प्रदेश आम महोत्सव-2023 का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महोत्सव का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मॉस्को, दुबई व बहरीन को निर्यात किये जाने वाले आम के ट्रकों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
- इसके तहत लखनऊ से 02 टन आम मॉस्को, 12 टन आम बहरीन और 01 टन आम दुबई निर्यात किया जा रहा है।
- मुख्यमंत्री ने उत्कृष्ट आम उत्पादक बागवानों, कृषकों व आम निर्यातकों को सम्मानित किया। साथ ही, उत्तर प्रदेश आम महोत्सव-2023 की स्मारिका का विमोचन किया।
- आम महोत्सव के माध्यम से किसानों और बागवानों की मेहनत व प्रदेश की औद्यानिक फसलों की संभावनाओं को देखने, समझने का अवसर प्राप्त हो रहा है।
- आम महोत्सव प्रदेश के कृषि उत्पादों को देश व दुनिया के बाज़ार में स्थान दिला रहा है। यह अन्नदाता किसानों की आय को बढ़ाने का एक मंच है।
- विदित है कि प्रदेश में आम की लगभग 01 हज़ार प्रजातियों का उत्पादन किया जाता है। इन आमों को जून से अगस्त माह तक प्रदेश सहित देशवासियों व दुनिया के अन्य देशों की मांग के अनुरूप आपूर्ति करने का कार्य किया जा रहा है।
- इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि उत्पादों व फसलों के निर्यात से हमारे अन्नदाता किसानों की आय को कई गुना बढ़ाने में मदद मिलेगी।

नोट :

- उल्लेखनीय है कि 07 से 09 जुलाई, 2023 को रूस की राजधानी मॉस्को में आयोजित आमरस महोत्सव में प्रदेश के कृषि विदेश व्यापार तथा कृषि निर्यात राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल सम्मिलित हुआ। इस प्रतिनिधिमंडल ने वहाँ प्रदेश के आम की प्रजातियों की मांग की संभावनाओं को देखा। उत्तर प्रदेश के आम की मांग यहाँ बहुत ज्यादा है।
- मॉस्को में 800 रुपए किलो के दाम पर प्रदेश के बागवानों/कृषकों के आम खरीदे जा रहे हैं। किसानों को प्रति किलो 600 रुपए का शुद्ध लाभ प्राप्त हो रहा है, जो यहाँ के बाज़ार मूल्य से कई गुना अधिक है। अपने कृषि उत्पादों को खाड़ी देशों व यूरोपीय देशों तक पहुँचाने का यह सबसे अच्छा समय है।

नोट :

लखनऊ में 3,300 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश वाली दो राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

17 जुलाई, 2023 को केंद्रीय सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश की राजधानी और देश के महत्त्वपूर्ण शहरों में से एक लखनऊ में 3,300 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश वाली दो राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- इन परियोजनाओं में मड़ियाँव-आई.आई.एम.राष्ट्रीय राजमार्ग 24 पर लखनऊ-सीतापुर खंड शामिल है। नवनिर्मित 4-लेन एलिवेटेड कॉरिडोर समय से छह महीने पहले पूरा हो गया है।
- इससे लखनऊ से सीतापुर तक बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी, भिटौली तिराहा और जानकीपुरम एक्सटेंशन पर भारी ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी और 30 मिनट से अधिक समय और ईंधन की बचत होगी। तीर्थयात्रियों को चंद्रिका देवी और नैमिषारण्य जाने में भी सुविधा होगी।
- अलीगढ़-कानपुर खंड के नवीगंज से मित्रसेनपुर तक 4-लेन सड़क के निर्माण से नवीगंज, कन्नौज, मित्रसेनपुर और आगे दिल्ली तक यातायात की सुविधा होगी। उत्तर प्रदेश के इत्र हब कन्नौज और आसपास के क्षेत्रों में आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
- छिबरामऊ, गुरसहायगंज, जलालाबाद, मानीमऊ जैसे इलाकों में छोटे और मझोले उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। कन्नौज के किसानों को छिबरामऊ, नवीगंज मंडी तक आवागमन में आसानी होगी और दिल्ली तक सीधी पहुँच आसान होगी।

नीति आयोग ने जारी की रिपोर्ट : गरीबी कम करने में उत्तर प्रदेश सभी राज्यों में अव्वल

चर्चा में क्यों?

17 जुलाई, 2023 को नीति आयोग ने सभी राज्यों की प्रगति के संबंध में मल्टीडाइमेंशनल पावर्टी इंडेक्स-2023 की नवीनतम रिपोर्ट जारी की, जिसमें उत्तर प्रदेश गरीबों की संख्या घटाने के मामले में पूरे देश में अव्वल रहा है।

प्रमुख बिंदु

- मल्टीडाइमेंशनल पावर्टी इंडेक्स-2023 की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार पूरे देश में गरीबी का प्रतिशत 24.85 से घटकर 14.96 प्रतिशत हो गया है। बहुस्तरीय गरीबी में शिक्षा स्वास्थ्य व जीवन स्तर के मानक भी शामिल हैं।
- उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ 42 लाख 72 हज़ार 484 लोग बहुस्तरीय गरीबी से बाहर आ गए हैं। इस कारण 2015-16 के मुकाबले 2019-21 में राज्य में कुल आबादी में गरीबों का प्रतिशत 37.68 से घटकर 22.93 हो गया है।
- इसके बाद बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा व राजस्थान गरीबी दूर करने में प्रमुख राज्य रहे हैं।
- बहुस्तरीय मानक पर गरीबों की संख्या प्रतिशत में :

गरीबी के मानक	वर्ष 2015-16	वर्ष 2019-21
पोषण	30.40	18.45
शिशु मृत्यु दर	3.81	2.20
मातृ स्वास्थ्य	25.20	15.97
स्कूल उपस्थिति	9.96	7.62
ईंधन	34.24	17.95
सफाई	31.74	11.91
पेयजल	2.09	0.93
बिजली	18.34	4.98
आवास	33.35	19.56
संपत्ति	8.86	4.22
बैंक खाते	4.8	2.96

- गरीबी में कमी वाले उत्तर प्रदेश के दस ज़िले:

ज़िले	आई कमी (प्रतिशत में)
महाराजगंज	-29.64
गोंडा	-29.55
बलरामपुर	-27.90
कौशांबी	-25.75
खीरी	-25.23
श्रावस्ती	-24.42
जौनपुर	-24.65
बस्ती	-23.36

नोट :

गाजीपुर	-22.83
कुशीनगर	-22.28
चित्रकूट	-21.40

अमेरिकी तकनीक से अलीगढ़ में बनेगी पिस्टल, रिवॉल्वर-कारतूस

चर्चा में क्यों ?

19 जुलाई, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रीयल कॉरिडोर अलीगढ़ नोड में अमेरिकन कंपनी स्मिथ एंड वेसन की तकनीक से इसी साल पिस्टल, रिवॉल्वर व कारतूस का निर्माण शुरू होगा। इसके लिये भारत की वेरीविन डिफेंस कंपनी ने अमेरिका की हथियार बनाने वाली स्मिथ एंड वेसन से करार किया है।

प्रमुख बिंदु

- अलीगढ़ के खैर तहसील के अंडला में निर्माणाधीन डिफेंस कॉरिडोर में कंपनी दिसंबर 2023 में हथियार आर्मी, पुलिस व निजी लोगों के लिये मार्केट में उतार देगी। अलीगढ़ नोड में कंपनी पिस्टल, रिवॉल्वर की सेल्स के लिये चेन का निर्माण शुरू कर दिया है।
- अलीगढ़ नोड में हथियारों का उत्पादन शुरू करने वाली वेरीविन डिफेंस पहली कंपनी होगी। कंपनी ने फैक्ट्री का निर्माण 90 फीसदी से अधिक पूरा कर लिया है। गोदाम से लेकर विस्फोटक सामग्री रखने के लिये स्टोर तैयार किये गए हैं। स्थानीय प्रशासन ने इसको लेकर लोगों से अनापत्ति भी मांगी है। पिस्टल, रिवॉल्वर व कारतूस के लाइसेंस गृह मंत्रालय से स्वीकृत हो चुके हैं।
- वेरीविन डिफेंस प्राइवेट लिमिटेड का मुख्य कार्यालय सिंगापुर में स्थित है।
- अमेरिकन कंपनी स्मिथ एंड वेसन के साझा करार में वेरीविन डिफेंस कंपनी सेना, पुलिस व निजी लोगों के लिये कई तरह की पिस्टल व रिवॉल्वर मार्केट में उतारेगी। कंपनी ने पिस्टल व रिवॉल्वर के मॉडल और खासियत जारी कर दी है। कीमत भी 1.70 लाख रुपए से अधिक की होगी। हालांकि अभी कंपनी इसमें निर्माण के बाद ही मूल्य निर्धारण करेगी, लेकिन प्राइमरी दरें तय कर दी गई हैं।
- वेरीविन डिफेंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अलीगढ़ की हार्डवेयर इकाइयों को भी काम देगी। डिफेंस कॉरिडोर में निवेश करने वाली यह एंकर इकाई है। लघु उद्योगों को इससे फायदा होगा। खासकर पहले रक्षा उत्पाद कर रहे निर्माताओं को काम मिलेगा।
- पिस्टल, कारतूस, रिवॉल्वर समेत अन्य रक्षा उपकरणों में छोटे-छोटे पार्ट्स की ज़रूरत होगी, जिसको सहायक इकाइयों से लिया जाएगा।
- उल्लेखनीय है कि वेरीविन ने अलीगढ़ में 85 करोड़ रुपए तो झांसी नोड में 127 करोड़ रुपए का निवेश किया है। अलीगढ़ में 4 एकड़ जमीन यूपीडा से ली गई है।

- वेरीविन डिफेंस कंपनी अलीगढ़ में हर माह दो लाख कारतूस बनाएगी। हालाँकि उत्पादन ऑर्डर के ऊपर निर्भर होगा, लेकिन क्षमता 2 लाख निर्माण की है।
- पुलिस व आर्मी के लिये 9 एमएम, सिविल के लिये 32, 45 व 380 एमएम की कारतूस बनेगी। कंपनी एक माह में 500 से अधिक हथियार का निर्माण करेगी। हथियार का निर्माण भी ऑर्डर पर ही निर्भर होगा। कंपनी की क्षमता 500 हथियार महीने की है।
- निदेशक वेरीविन डिफेंस प्राइवेट लिमिटेड, मोहित शर्मा ने बताया कि वेरीविन डिफेंस कंपनी शस्त्र निर्माण के क्षेत्र में 40 सालों से काम कर रही है।

प्रदेश में खेल नीति के तहत सभी विद्यालयों में चालीस मिनट के खेल अनिवार्य

चर्चा में क्यों ?

19 जुलाई, 2023 को उत्तर प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गिरीश चंद्र यादव ने बताया कि खेल नीति के तहत प्रदेश के सभी विद्यालयों में चालीस मिनट के खेल अनिवार्य कर दिये गए हैं।

प्रमुख बिंदु

- खेल एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गिरीश चंद्र यादव ने बताया कि इसका उद्देश्य बच्चों में खेलों के प्रति दिलचस्पी बढ़ाना और उनका शारीरिक व बौद्धिक विकास करना है।
- विदित है कि 10 मार्च, 2023 को उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने प्रदेश में खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने तथा खेल संस्कृति विकसित करने हेतु राज्य की पहली खेल नीति-2023 को हरी झंडी दी थी।
- नई खेल नीति में खिलाड़ियों की शारीरिक दक्षता से लेकर उनकी ट्रेनिंग तक का खास ख्याल रखा गया है। इसके साथ ही भारतीय खेल प्राधिकरण की तर्ज पर 'राज्य खेल प्राधिकरण'का गठन भी किया जाएगा तथा निजी अकादमियों और स्कूल-कॉलेजों को खेलों से जोड़ा जाएगा।
- इसके अलावा इस नीति के तहत हर विद्यालय में 40 मिनट का समय खेल, शारीरिक शिक्षा या योग के लिये निर्धारित किया गया है। राज्य में पीपीपी के तहत अलग-अलग खेलों के 14 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तैयार किये जाएंगे तथा राज्य में पाँच हाई परफारमेंस सेंटर स्थापित किये जाएंगे।

अब जीवित साहित्यकारों पर भी कर सकेंगे पीएचडी, CSJMU कानपुर तैयार कर रहा लिस्ट

चर्चा में क्यों?

23 जुलाई, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के कानपुर स्थित छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय (CSJMU) नई पहल करते हुए अब जीवित साहित्यकारों पर भी पीएचडी कराएगा। इसके लिये जाने-माने साहित्यकारों की सूची तैयार की जा रही है, फैसला इसी सत्र से लागू किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- विदित है कि अभी तक उन साहित्यकारों पर शोध किया जाता है, जो इस दुनिया में नहीं हैं।
- सीएसजेएमयू कुलपति प्रो. विनय पाठक के निर्देशन में प्रस्ताव तैयार किया गया है।
- विवि में बने दीनदयाल शोध केंद्र में भी अब पीएचडी होगी। इस पर अंतिम मुहर लग चुकी है। यहाँ देश व समाज के लिये उत्कृष्ट कार्य करने वाली चार विभूतियों पर पीएचडी कराई जाएगी।
- इनमें एकात्म मानववाद का संदेश देने वाले दीनदयाल उपाध्याय, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, संविधान के रचयिता डॉ. भीमराव आंबेडकर और सामाजिक मतभेद मिटाने वाले छत्रपति शाहू जी महाराज के नाम शामिल हैं।
- गौरतलब है कि कई पूर्व छात्रों ने विवि का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। इनमें भारतरत्न अटल बिहारी वाजपेयी, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, प्रख्यात कवि गोपाल दास नीरज समेत कई वैज्ञानिक, राजनेता व देश की विभिन्न कंपनियों में उच्च पदों पर दिग्गज लोग विराजमान हैं।

मुख्यमंत्री ने 72 करोड़ के 42 विकास कार्यों का किया शिलान्यास

चर्चा में क्यों?

23 जुलाई, 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के गोरखनाथ क्षेत्र के भाटी विहार में अपनी विधायक निधि से मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और रामगढ़ताल रिंग रोड समेत 42 परियोजनाओं का शिलान्यास किया।

प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने गरीबों के मांगलिक समारोहों की भव्यता से आयोजन के लिये कल्याण मंडपम बनाने का ऐलान किया। ये कल्याण मंडपम सभी सुविधाओं से युक्त होंगे।
- मुख्यमंत्री ने नगर निगम और गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) को कल्याण मंडपम की स्थापना करने का निर्देश दिया है।
- शुरुआत में गोरखपुर शहर में छह अलग-अलग स्थानों पर कल्याण मंडपम बनाए जाएंगे। कल्याण मंडपम की स्थापना में एक से डेढ़ करोड़ की लागत आएगी। यहाँ शादी व मांगलिक कार्यक्रमों के लिये हॉल, रूम, गेस्ट रूम, पार्किंग, ढाई-तीन सौ लोगों की क्षमता का लॉन आदि सभी ज़रूरी सुविधाएँ होंगी।
- इसके अलावा मुख्यमंत्री ने गोरखपुर को अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोरखपुर में पूर्वी उत्तर प्रदेश के पहले मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की स्थापना के साथ बाघागाड़ा के पास 150 एकड़ क्षेत्रफल में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का भी निर्माण कराया जाएगा।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के हर ज़िले में स्टेडियम, हर विकास खंड में मिनी स्टेडियम, ग्राम पंचायत में खेल का मैदान, गाँवों व पार्कों में ओपन जिम की स्थापना से खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है।
- ओलंपिक, एशियाड, कॉमनवेल्थ, विश्व चैंपियनशिप में पदक विजेताओं को नकद पुरस्कार देने के साथ सरकारी नियुक्ति से भी जोड़ा जा रहा है। हाल में 500 खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। पुलिस विभाग में डिप्टी एसपी से लेकर कॉन्स्टेबल तक के पदों पर खिलाड़ियों को नौकरी मिल रही है।

नोट :

- मुख्यमंत्री ने जीडीए द्वारा कराए जाने वाले 63 बेसिक प्राथमिक विद्यालयों के कायाकल्प का उल्लेख करते हुए कहा कि जर्जर हो चुके इन स्कूलों में भवन, फ्लोरिंग, फर्नीचर, शौचालय, शुद्ध पेयजल, स्मार्ट क्लास व लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। कायाकल्प के बाद ये स्कूल कॉन्वेंट को भी फेल करते नजर आएंगे।

जगजीवन आरपीएफ अकादमी लखनऊ में नवनिर्मित राष्ट्रीय शहीद स्मारक का अनावरण

चर्चा में क्यों?

24 जुलाई, 2023 को रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक संजय चंदर ने जगजीवन आरपीएफ अकादमी लखनऊ में नवनिर्मित राष्ट्रीय शहीद स्मारक एवं राष्ट्रीय रेलवे सुरक्षा संग्रहालय का अनावरण किया।

प्रमुख बिंदु

- विदित है कि यह शहीद स्मारक 4800 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और इस स्मारक पर 1957 से अब तक 1014 शहीद आरपीएफ कर्मियों के नाम अंकित किये गए हैं और आरपीएफ की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि दी गई है।
- इस संग्रहालय में आने वाले पर्यटक को एक ही नज़र में रेलवे सुरक्षा बल के इतिहास, उत्पत्ति, उपलब्धियों, कर्तव्यों और ज़िम्मेदारियों की पूरी जानकारी मिल जाएगी।
- संग्रहालय कुल 9000 वर्ग फुट क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें 37 विषयगत डिस्प्ले पैनल, 11 डिस्प्ले कैबिनेट, पुलिस प्रणाली का इंफोग्राफिक इतिहास, 87 कलाकृतियाँ, भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार से 500 पृष्ठ, बीते युग के 36 हथियार, सुरक्षा से संबंधित 150 रेलवे की वस्तुएँ, रेलवे सुरक्षा बल के विभिन्न रैंकों के 15 पुतले और कई अन्य महत्त्वपूर्ण वस्तुएँ प्रदर्शित हैं।

- इस संग्रहालय का आदर्श वाक्य 'ज्ञानवर्धनायचसंरक्षणाय' है, जो आरपीएफ को 'ज्ञान को बढ़ावा देने और विरासत को संरक्षित करने' के लिये लगातार प्रेरित करता है।
- इसके अलावा, रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक ने सेंट्रल आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल डिपो किर्की, खड़की, पुणे से प्राप्त और अकादमी परिसर में स्थापित वॉर ट्रॉफी टी-55 टैंक, नवनिर्मित बैडमिंटन और लॉन टेनिस कोर्ट, आरपीएफ के विशेष बैंड का भी अनावरण किया।

बीएचयू के डॉ. अमिय कुमार समल राष्ट्रीय युवा भूवैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित

चर्चा में क्यों?

24 जुलाई, 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित एक भव्य समारोह में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी के भूविज्ञान विभाग में सहायक प्रोफेसर डॉ. अमिय कुमार समल को खान मंत्रालय के प्रतिष्ठित राष्ट्रीय युवा भूवैज्ञानिक पुरस्कार- 2022 (एनजीए) से सम्मानित किया।

प्रमुख बिंदु

- विदित है कि राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार- 2022 (एनजीए) में देश भर के कामकाजी पेशेवरों और शिक्षाविदों सहित 22 भूवैज्ञानिकों ने तीन श्रेणियों-लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिये एक राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार, एक राष्ट्रीय युवा भूवैज्ञानिक पुरस्कार और भूविज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में आठ राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार के तहत सम्मान हासिल किया।
- लाइफटाइम अचीवमेंट के लिये राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार डॉ. ओम नारायण भार्गव (मानद प्रोफेसर, भूविज्ञान विभाग पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़) को दिया गया। वह पिछले चार दशकों में हिमालय में अपने उल्लेखनीय कार्य के लिये जाने जाते हैं।
- बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर डॉ. अमिय कुमार समल को भारतीय सतह के विभिन्न आर्कियन क्रेटन के नीचे उप-महाद्वीपीय लिथोस्फेरिक मेंटल (एससीएलएम) की विविधता को समझने में उनके महत्त्वपूर्ण योगदान के लिये राष्ट्रीय युवा भूवैज्ञानिक पुरस्कार प्रदान किया गया है।
- उल्लेखनीय है कि 1966 में शुरू हुए राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार (एनजीए) उन असाधारण लोगों और संगठनों के लिये सम्मान और प्रशंसा का प्रतीक है, जिन्होंने भूविज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्टता, समर्पण और नवाचार का प्रदर्शन किया है। ये पुरस्कार खनिजों की खोज और अन्वेषण, बुनियादी भूविज्ञान, अनुप्रयुक्त भूविज्ञान और खनन, खनिज अधिशोधन और सतत् खनिज विकास के क्षेत्र में प्रदान किये जाते हैं।

- राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार-2022 के लिये कुल 173 नामांकन प्राप्त हुये थे। तीन पुरस्कार श्रेणियों के तहत वैध नामांकनों की संख्या 168 है। कुल 12 पुरस्कारों में से, एएमए ने अंततः 10 पुरस्कारों का चयन किया है, जिनमें 4 व्यक्तिगत पुरस्कार, 3 टीम पुरस्कार और 3 संयुक्त पुरस्कार शामिल हैं। 4 व्यक्तिगत पुरस्कारों में लाइफटाइम अचीवमेंट के लिये राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार के वास्ते एक पुरस्कार और राष्ट्रीय युवा भूवैज्ञानिक पुरस्कार के लिये एक अन्य पुरस्कार भी शामिल है।

क्र. सं.	पुरस्कार की श्रेणी	पुरस्कारों की संख्या
1.	लाइफटाइम अचीवमेंट के लिये राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार	1 पुरस्कार
2.	राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक पुरस्कार	8 पुरस्कार (3 टीम पुरस्कार+3 संयुक्त पुरस्कार + 2 व्यक्तिगत पुरस्कार = 20 पुरस्कार विजेता)
3.	राष्ट्रीय युवा भूवैज्ञानिक पुरस्कार	1 पुरस्कार
	कुल	**10 पुरस्कार (22 पुरस्कार विजेता)**

उत्तर प्रदेश में स्थापित होगा आपदा राहत प्रशिक्षण केंद्र

चर्चा में क्यों?

26 जुलाई, 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आपदा प्रबंधन कार्यों की समीक्षा के दौरान बताया कि प्रदेश में आपदा राहत प्रशिक्षण केंद्र स्थापित होगा। साथ ही बरेली व झाँसी में क्षेत्रीय रेस्पांस सेंटर की स्थापना की जाएगी।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री ने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के बीच परस्पर समन्वय के साथ प्रदेश में आपदा प्रबंधन के कार्यों को प्रभावी बनाने के लिये जारी प्रयासों की समीक्षा के दौरान जरूरी निर्देश दिये।
- उन्होंने निर्देश दिये कि आपदाकाल में राहत कार्यों के लिये योग्य व कुशल कार्मिकों की उपलब्धता पहली जरूरत है। जितने दक्ष कार्मिक होंगे, राहत कार्य उतना प्रभावी होगा। इसके लिये सेंटर स्थापित करना ज़रूरी है। इसमें एनडीआरएफ से भी सहयोग लिया जाना चाहिये। आकाशीय बिजली से होने वाली ऐसी जनहानि को कम करना बड़ी चुनौती है।
- विदित है कि वर्ष 2022-23 में 301 व 2023-24 में अब तक 36 ज़िलों में 174 मौतें हुई हैं।
- उन्होंने निर्देश दिये कि तीन माह में 75 ज़िलों में अर्ली वार्निंग सिस्टम लगा दिये जाएँ। इस तकनीक से आकाशीय बिजली गिरने के तीन से चार घंटे पहले पता लगाया जा सकता है, एक घंटे पहले सटीक स्थान की जानकारी मिल सकती है। समय से जानकारी मिलने पर जन व धन की हानि नहीं होगी।
- केंद्र सरकार द्वारा विकसित कराए गए दामिनी एप, मेघदूत जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म का प्रचार-प्रसार किया जाए।
- मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश के सभी ज़िलों में इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर स्थापित किये गए हैं। इन्हें सेफ सिटी के तहत आईसीसीसी से इंटीग्रेट किया जाए।
- सभी ग्राम पंचायतों और नगरीय निकायों में पब्लिक एड्रेस सिस्टम को स्थापित कराएँ। इन्हें अर्ली वार्निंग सिस्टम से जोड़ा जाए। आपदाकाल में आपदा मित्रों की भूमिका बहुत महत्त्वपूर्ण है। शेष ज़िलों में इनकी तैनाती की जाए।

उत्तर प्रदेश के 74 ज़िलों में खुलेंगे क्रिटिकल केयर यूनिट

चर्चा में क्यों ?

26 जुलाई, 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया की उपस्थिति में बताया कि प्रदेश में 'एक जनपद, एक मेडिकल कॉलेज' का संकल्प पूरा करने की दिशा में 74 ज़िलों में क्रिटिकल यूनिट स्थापित की जाएगी।

प्रमुख बिंदु

- विदित है कि प्रदेश में 45 ज़िलों में सरकारी मेडिकल कॉलेज क्रियाशील हैं। जल्द ही प्रदेश के 13 ज़िलों में मेडिकल कॉलेज का शुभारंभ होने वाला है।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को और मजबूत करने की ज़रूरत है। हर मेडिकल कॉलेज को न्यूनतम पाँच कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को गोद लेना चाहिये। वहाँ नियमित अंतराल पर डॉक्टरों को विजिट करना चाहिये और सेंटर के डॉक्टरों का मार्गदर्शन करना चाहिये।
- प्रधानमंत्री आयुष्मान हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर योजना के तहत प्रत्येक ज़िले में गंभीर बीमारियों के उपचार के लिये ज़िला स्तरीय अस्पताल या मेडिकल कॉलेज में 100 या 50 बेड के क्रिटिकल केयर ब्लॉक की स्थापना की जाएगी।
- केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि तमिलनाडु ऐसा राज्य है, जहाँ एक दिन में 11 मेडिकल कॉलेज लोकार्पित हुए थे। अब 13 मेडिकल कॉलेजों के लोकार्पण के साथ उत्तर प्रदेश नया रिकॉर्ड बनाएगा।
- ज्ञातव्य है कि आजादी के बाद अब तक प्रदेश में राजकीय क्षेत्र में मात्र पाँच बीएससी नर्सिंग कॉलेज संचालित थे। वर्ष 2021-22 में सात तथा 2022-23 में 11 नए राजकीय नर्सिंग कॉलेज संचालित किये गए।
- भारत सरकार के सहयोग से यहाँ अतिशीघ्र 27 नए नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना होने जा रही है। इससे प्रदेश के नर्सिंग और पैरामेडिकल सेक्टर में कैरियर बनाने के इच्छुक युवाओं के लिये बड़ा अवसर सृजित होगा।
- केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि भारत सरकार सितंबर से 'आयुष्मान भव:' अभियान प्रारंभ कर रही है। इसके तहत 'आपके द्वार आयुष्मान 3.0' कार्यक्रम होगा।
- कार्यक्रम में घर-घर जाकर आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे। गांवों, नगरों और स्कूलों में 'आयुष्मान सभा' के आयोजन होंगे। इस प्रकार जो गांव पूरी तरह संतृप्त हो जाएगा, उसे 'आयुष्मान ग्राम' घोषित किया जाएगा।

नोट :

- प्रस्तावित 'आयुष्मान भव:' अभियान की सफलता के लिये राज्य में सभी जरूरी प्रयास करने के निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि उत्तर प्रदेश सर्वाधिक 'आयुष्मान ग्राम' वाला राज्य होगा।
- आयुष्मान भारत के तहत अब उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सत्यापित कर उपलब्ध कराये गए डाटा के आधार पर भी लाभार्थियों को योजना का लाभ दिया जाएगा। राज्य सरकार जिन परिवारों को सत्यापित कर डाटा उपलब्ध कराएगी, सभी को आयुष्मान भारत कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा।
- केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने कहा कि चंदौली में ट्रॉमा सेंटर की स्थापना के लिये भारत सरकार ने 16.81 करोड़ रुपए स्वीकृत किये हैं। वहीं वाराणसी में श्री शिवप्रसाद गुप्त मंडलीय व ज़िला चिकित्सालय में मल्टी सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल स्थापित करने के लिये 215.62 करोड़ रुपए स्वीकृत किये गए हैं।